संख्या-02 /2023-210/58-2023-100(2)/2001

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

एवं जनपदीय लाइसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह),

उत्तर प्रदेश ।

उद्यान अनुभाग / लखनऊ : दिनाँक 27 जनवरी, 2023

विषय :- आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस वर्ष अभी तक मौसम के अनुकूल रहने से प्रदेश में आलू की अधिक पैदावार होने की संभावना बनती जा रही है। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि आलू का समय से भण्डारण सुनिश्चित कराने के लिए निजी शीतगृहों के संचालन हेतु निम्न बिन्दुओं पर आपके स्तर पर अविलम्ब समीक्षा कर ली जाए :-

1. वर्ष 2023 के लिए जनपद में सभी चालू शीतगृहों का लाइसेंस नवीनीकरण हो गया है। जनपद में कोई भी शीतगृह बिना लाईसेन्स नवीनीकरण के न चलने पाये । प्रायः देखा गया है कि बिना लाईसेन्स नवीनीकरण के शीतगृहों द्वारा आलू भण्डारित कर लिया जाता है और भण्डारणकर्ताओं के आलू में क्षति होने पर वाद / विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है।

2. जनपद में सभी चालू शीतगृहों का लाइसेंस नवीनीकरण करते समय भवन एवं मशीनरी का बीमा, कम्प्रेशर तथा जनरेटर की स्टेण्ड बाई व्यवस्था, शीतगृह भवन एवं मशीनरी (अवशीतन प्रणाली) की सुदृढ़ता के सम्बन्ध में सक्षम अभियन्ता का वैधानिक प्रमाण-पत्र हो । इसके अतिरिक्त निजी शीतगृहों में भवन एवं मशीनरी की खराबी के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने वाले आलू के बचाव के लिये शासनादेश संख्या - 5701 / 58-1-2000 दिनांक 20 दिसम्बर 2000 एवं

http://shasanadesh.up.gov.in

निदेशालय उद्यान के पृष्ठांकन सं0-1974 दिनांक 06 जनवरी 2001 के क्रम में अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

3. जो शीतगृह किन्हीं कारणोंवश बन्द हैं, उन्हें आगामी भण्डारण सत्र हेतु चालू करने पर यथोचित कार्यवाही प्राथमिकता पर करा ली जाय ।

4. शीतगृह में आलू भण्डारण के समय लगने वाली लम्बी कतार एवं सड़क जाम की समस्या के निदान हेतु शासनादेश संख्या - 3532 /58-1- 98–100(28)/98, दिनाँक 16-10–98 द्वारा शीतगृहों की भण्डारण क्षमता के सापेक्ष लाइसेंसधारियों की बुकिंग प्रक्रिया समय से प्रारम्भ की जाय। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भण्डारण क्षमता के 85 प्रतिशत की बुकिंग होने पर भरपूर प्रचार-प्रसार कराया जाय ।

5. शासनादेश-385/58-1-2000 (2)/2001, दिनाँक 29-01-2001 द्वारा आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में आलू किसान अधिकार पत्र जारी किया गया है जिसे समस्त शीतगृहों पर 2X4 फिट के आकार के नोटिस बोर्ड पर पठनीय भाषा में लिखवाकर प्रत्येक शीतगृह के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसी के साथ-साथ उद्यान निदेशालय के पत्र संख्या- आलू - 1942 / शीतगृह, दिनाँक 14-02-02 द्वारा किसान अधिकार पत्र के बिन्दु - 04 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम - 1976 की धारा - 22 के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करा लिया जाय ।

6. आलू भण्डारण से पूर्व जनपद के प्रत्येक शीतगृह में वर्ष 2023 के लिए निर्धारित किये गये भण्डारण प्रभार की सूचना अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा शीतगृह के मुख्य प्रवेश द्वार एवं सूचना पट पर भण्डारण प्रभार की दर अवश्य प्रदर्शित कर दिया जाय ।

7. भण्डारणकर्ताओं को शीतगृह पर आलू पहुँचाने के समय शीतगृह अधिनियम 1976 में वर्णित प्रारूप में तकपट्टी तुरन्त उपलब्ध करा दी जाय तथा शासनादेश संख्या - 3532 / 58-1-98–100 (28) / 98, दिनाँक 16-10-1998 के पैरा-8 के अनुपालन में तकपट्टी पर तौल एवं भण्डारण प्रभार दर भी लिखे जाने का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

8. उ०प्र० शीतगृह विनियमन अधिनियम, 1976 एवं इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश तथा किसान अधिकार पत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. अग्निशमन विभाग द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2019 को जारी दिशा-निर्देश प्रदेश के नये शीतगृहों /कोल्ड स्टोरेज के लिए लागू होंगे। पुराने शीतगृहों में अग्निशमन विभाग द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे ।

10. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंसकरण विभाग, उ०प्र० के पत्र संख्या-आलू 967 दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 द्वारा जारी निर्देश के अनुसार शीतगृह में भण्डारित किये जाने वाले कृषि उत्पाद का कृषि उत्पादन मण्डी समिति की निर्धारित दरों के अनुसार अप्रैल माह में स्टॉक का बीमा अवश्य करा लिया जाय ।

अतः उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अभी से रणनीति बना ली जाय, ताकि आलू भण्डारणकर्ताओं को शीतगृह में कोई असुविधा न हो ।

कृपया कृत कार्यवाही से शासन तथा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव ।

<u>संख्या- 02 /2023-210(1)/58-2023/ तद्दिनांकित</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश |
2- निजी सचिव, मा० उद्यान मंत्री, उ०प्र० शासन ।
3- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र० शासन ।
5- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- समस्त उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश |
7- समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8- गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in